प्रारंभिक परीक्षा

भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश

संदर्भ

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने सरकार से **भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नाम की सिफारिश की है।**

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में -

- **अनुच्छेद-124(2) के तहत CJI की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।**
- केंद्रीय कानून मंत्रालय भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निवर्तमान CJI की सिफारिश मांगता है।
- निवर्तमान CJI से सिफारिश प्राप्त होने के बाद, केंद्रीय कानून मंत्रालय प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजता है।
- इसके बाद वह नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
- **आम तौर पर निवर्तमान CJI अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं।**

क्या आप जानते हैं?

- सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की परिपाटी को आज तक 3 बार तोड़ा जा चुका है।
- **संविधान में सर्वोच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।**
- **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं**:
    - वह भारत का नागरिक हो।
    - उसके पास एक उच्च न्यायालय या दो या अधिक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।
    - वह किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
    - वह राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।

स्रोत: The Hindu - CJI

टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट(Tensor Processing Unit)

संदर्भ

गूगल ने हाल ही में अपनी **सातवीं पीढ़ी की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट(TPU) आयरनवुड लॉन्च की है**।

TPU के बारे में -

- **TPU एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स(ASICs) हैं, जो विशेष रूप से मशीन लर्निंग (ML) कार्यों, जैसे डीप लर्निंग, को गति देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।**
- इन्हें विशेष रूप से टेंसर (एमएल मॉडल में प्रयुक्त मल्टी-डायमेंशनल ऐरे) से जुड़े कार्यों को संभालने के लिए बनाया गया है।

TPU की मुख्य विशेषताएं -

- **मशीन लर्निंग के लिए डिज़ाइन किया गया:** टेंसर ऑपरेशन के लिए अनुकूलित, जो न्यूरल नेटवर्क की नींव हैं।
- **उच्च प्रदर्शन:** TPU एमएल कार्यों के लिए CPU और GPU की तुलना में काफी तेज गणना प्रदान करते हैं।
    - GPU पर जो प्रशिक्षण सप्ताहों में पूरा हो जाता है, उसे TPU का उपयोग करके घंटों में पूरा किया जा सकता है।
- **समानांतरता:** GPU की तरह, TPU भी समानांतर प्रसंस्करण का उपयोग करते हैं, लेकिन वे और भी अधिक विशिष्ट होते हैं। वे एक साथ लाखों टेंसर संचालन को संभाल सकते हैं।
- **ऊर्जा दक्षता:** AI कार्यभार चलाते समय GPU और CPU की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल।

CPU, GPU और TPU के बीच मुख्य अंतर -

विशेषता	**सेंट्रा प्रोसेसिंग यूनिट**	**ग्राफ़िक प्रोसेसिंग यूनिट**	**टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट**
उद्देश्य	सामान्य कंप्यूटिंग	ग्राफ़िक्स और समानांतर कंप्यूटिंग	AI और ML-विशिष्ट कार्य
प्रसंस्करण प्रकार	अनुक्रमिक	समानांतर	टेंसर-आधारित, समानांतर
एआई में दक्षता	कम	उच्च	बहुत उच्च

स्रोत: **Indian Express - TPU**

समाचार संक्षेप में

टाइप-5 मधुमेह(Type-5 Diabetes)

- अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ (IDF) ने टाइप 5 मधुमेह को अत्यधिक चीनी के बजाय कुपोषण से उत्पन्न रोग माना है।

टाइप-5 मधुमेह क्या है?

- **यह कुपोषण से संबंधित मधुमेह है, जो आम तौर पर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दुबले-पतले और कुपोषित किशोरों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है।**
- यह गर्भ से ही शुरू हो जाता है, जिससे अग्न्याशय का खराब विकास होता है।
- **अग्न्याशय पर प्रभाव**: अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं बहुत कम इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, जिसका कारण ऑटोइम्यूनिटी (जैसा कि टाइप 1 में होता है) या इंसुलिन प्रतिरोध (जैसा कि टाइप 2 में होता है) नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि दीर्घकालिक कुपोषण के कारण अग्नाशय कभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता।
- **इसे पहली बार जमैका (1955) में J-टाइप मधुमेह के रूप में पहचाना गया था।**

स्रोत: Indian Express - Type-5 Diabetes

सिल्कयारा सुरंग

- **अवस्थिति:** उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर।
- **यह सुरंग चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है।**
- **यह 4.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग है। (उत्तराखंड की सबसे बड़ी सुरंग)।**
- इसके पूरा होने पर गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 31.5 किलोमीटर कम हो जाएगी।
- 2023 में सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, 41 मजदूर 17 दिनों तक अंदर फंसे रहे थे।

स्रोत: Indian Express - Silkyara

कैलाश मानसरोवर यात्रा

- भारत और चीन कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने के प्रयासों में तेज़ी ला रहे हैं।
- कोविड-19 महामारी (2020-2022) और गलवान झड़प (2020) के बाद भारत-चीन तनाव के कारण इसे 2019 से निलंबित कर दिया गया है।

कैलाश मानसरोवर के बारे में -

- **यह तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र की पश्चिमी हिमालय पर्वतमाला में एक पवित्र तीर्थ स्थल है।**
- **इसमें कैलाश पर्वत (कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी) और मानसरोवर झील (दुनिया की सबसे ऊँची मीठे पानी की झील) शामिल हैं।**
- इसे हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन्पो पवित्र पर्वत मानते हैं।
- यात्रा दो अलग-अलग मार्गों से सुलभ है:
  - लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड)
  - नाथू ला दर्रा (सिक्किम)।

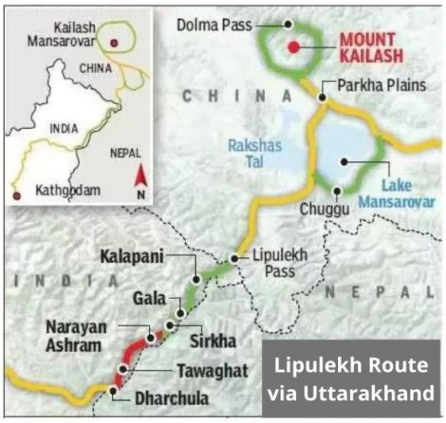
Kailash Mansarovar
CHINA
INDIA
NEPAL
Kathgodam
N
Dolma Pass
MOUNT KAILASH
C H I N A
Parkha Plains
Rakshas Tal
Lake Mansarovar
Chuggu
Kalapani
Lipulekh Pass
I N D I A
N E P A L
Gala
Narayan Ashram
Sirkha
Tawaghat
Dharchula
Lipulekh Route via Uttarakhand

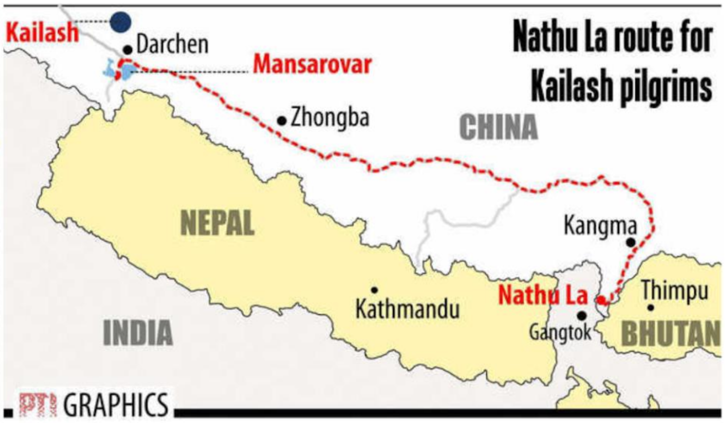
Kailash
Darchen
Mansarovar
Zhongba
Nathu La route for Kailash pilgrims
CHINA
NEPAL
Kangma
Kathmandu
Nathu La
Thimpu
INDIA
Gangtok
BHUTAN
PTI GRAPHICS

स्रोत: The Hindu - KMY

दस्तलिक - VI

- **यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो प्रत्येक देश में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।**
- इसका छठा संस्करण 16 से 28 अप्रैल 2025 तक पुणे के औंध में आयोजित किया जाना है।
- यह संस्करण अर्ध-शहरी परिदृश्य में संयुक्त बहु-डोमेन उप-पारंपरिक संचालन पर केंद्रित होगा।

स्रोत: PIB - DUSTLIK-VI

भारत का पहला फुल-स्टैक क्वांटम कंप्यूटर

- हाल ही में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QpiAI ने 25 क्यूबिट वाला फुल-स्टैक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है।

QpiAI-इंडस के बारे में -

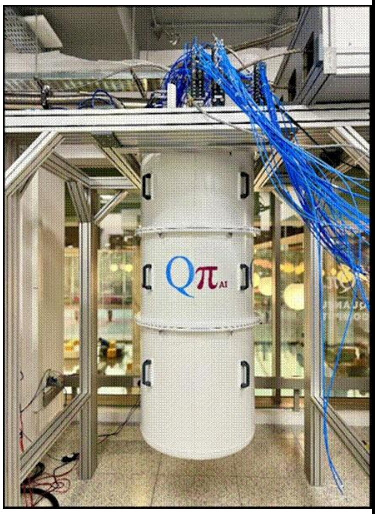

- **यह यह भारत का पहला पूर्ण-स्टैक क्वांटम सिस्टम है, जो क्वांटम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एआई-संवर्धित हाइब्रिड कंप्यूटिंग को एकीकृत करता है।**
- **तकनीकी निर्देश:**
  - **क्यूबिट गणना:** 25 सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट.
  - **आर्किटेक्चर**: **फुल-स्टैक क्वांटम सिस्टम** एकीकृत:
    - उन्नत क्वांटम हार्डवेयर
    - स्केलेबल नियंत्रण प्रणालियाँ
    - अनुकूलित सॉफ्टवेयर स्टैक
  - यह हाइब्रिड कंप्यूटिंग (क्वांटम + क्लासिकल) का समर्थन करता है।
  - इसमें सुपरकंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर का उपयोग किया गया है।

स्रोत: PIB - Supercomputer

काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर (CCyB)

- **CCyB एक विनियामक उपकरण है जो बैंकों को अच्छे समय में पूंजी बफर बनाने के लिए अनिवार्य बनाता है ताकि वे घाटे को अवशोषित कर सकें और आर्थिक मंदी के दौरान ऋण प्रवाह को बनाए रख सकें।**
- **उद्देश्य**:

  - संकट के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र में ऋण प्रवाह बनाए रखना।
  - अत्यधिक ऋण वृद्धि के समय अंधाधुंध ऋण देने पर अंकुश लगाना।
  - बैंकिंग क्षेत्र की लचीलापन क्षमता को बढ़ाना।
- **मुख्य संकेतक**: ऋण-से-जीडीपी अंतर प्राथमिक मीट्रिक है, जिसका उपयोग पूरक संकेतकों के साथ किया जाता है।
- **इसे आरबीआई द्वारा 2015 में बेसल III के तहत पेश किया गया था, लेकिन अब तक इसका उपयोग नहीं किया गया।**

स्रोत: **Deccan Herald - CCyB**

थांगजिंग हिल्स

- हाल ही में कुकी-ज़ो समुदाय के विरोध के कारण मैतेई तीर्थयात्रियों को मणिपुर में थांगजिंग पहाड़ियों की अपनी वार्षिक तीर्थयात्रा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

थांगजिंग हिल्स के बारे में -

- **अवस्थिति:** मणिपुर का चुराचांदपुर जिला, मोइरांग शहर के पश्चिम में।
- यह पहाड़ी मणिपुरी लोगों, विशेषकर मोइरांग क्षेत्र के लोगों द्वारा एक पवित्र स्थल माना जाता है।
- मैतेई समुदाय देवता की भक्ति में हर वर्ष पहाड़ी की चोटी तक तीर्थयात्रा करता है।

स्रोत: **TOI - Thangjing Hills**

संपादकीय सारांश

जनजातीय लोगों का आंतरिक विस्थापन

संदर्भ

2005 में लगभग 50,000 गोंड आदिवासियों को छत्तीसगढ़ से तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश(अब तेलंगाना का हिस्सा) में पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था।

उन्हें विस्थापित क्यों किया गया?

- **माओवादियों से निपटने के लिए रणनीतिक हेमलेटिंग (2005):** भारत सरकार ने माओवादियों की उपस्थिति को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में एक "रणनीतिक हेमलेट" कार्यक्रम (वियतनाम युद्ध मॉडल से प्रेरित) शुरू किया।
    - सुरक्षा और निगरानी के लिए आदिवासियों को जबरन उनके वन घरों से सड़क किनारे के शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया।
    - इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ।
- **माओवादियों का डर:** कुछ आदिवासी माओवादियों के प्रतिशोध के डर से घर वापस नहीं लौटे।
    - माओवादी अक्सर उन आदिवासियों को धमकाते या निशाना बनाते थे जो सरकारी बलों का समर्थन या सहयोग करते देखे जाते थे।
- **बस्तर क्षेत्र में जारी हिंसा:** प्रारंभिक झड़प के बाद भी माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा जारी रही।
    - बस्तर क्षेत्र में चल रहे सशस्त्र संघर्ष के कारण, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, लगातार विस्थापन हो रहा है।
- **उपेक्षा और पुनर्वास से इनकार:** छत्तीसगढ़ सरकार ने विस्थापन से इनकार करते हुए दावा किया कि हिंसा के कारण कोई भी आदिवासी पलायन नहीं कर रहा है।
    - आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) का कोई उचित सर्वेक्षण या मान्यता नहीं थी, जिससे पुनर्वास या पुनर्स्थापन में देरी हो रही थी।

भारत के अन्य भागों में सामरिक हेमलेट रणनीति

सामरिक **हेमलेट रणनीति**, जिसमें उग्रवाद को नियंत्रित करने और आतंकवादियों को अलग-थलग करने के लिए ग्रामीण आबादी को स्थानांतरित करना शामिल है, का उपयोग भारत के अन्य क्षेत्रों में भी किया गया है, हालांकि इसके परिणाम अलग-अलग रहे हैं:

तेलंगाना (1940 के दशक के अंत से 1950 के दशक के प्रारंभ तक)

- हैदराबाद के एकीकरण के बाद कम्युनिस्ट विद्रोह (तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष) का मुकाबला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।
- आदिवासियों को सड़क किनारे शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया।
- सैकड़ों आदिवासियों को कोया "टाइगर स्क्वायड" की तरह "विशेष पुलिस कांस्टेबल" के रूप में भर्ती किया गया था।
- भालों और कुल्हाड़ियों से लैस होकर, उन्होंने कम्युनिस्ट समूहों (दलम) से लड़ने में सहायता की।

मिज़ोरम (1960 – 1980)

- मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।
- हजारों ग्रामीणों को जबरन "संरक्षित गांवों" (रणनीतिक बस्तियों) में स्थानांतरित कर दिया गया।
- विद्रोहियों के समर्थन आधार को खत्म करने में मदद की।
- 1986 में शांति समझौता हुआ, जिससे उग्रवाद समाप्त हो गया।

वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?

- **कानूनी संरक्षण का अभाव:** भारत में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे का अभाव है।
    - जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने और इसलिए आधार नहीं होने से बच्चे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य हो जाते हैं। (केजीबीवी) स्कूल।
- **नई बस्तियों में शत्रुतापूर्ण व्यवहार:** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उन्हें "अतिक्रमणकारी" या प्रवासी के रूप में देखा जाता है।
    - उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया और उन्हें जनजातीय दर्जा देने से इनकार कर दिया गया , भले ही उनमें से कई का जन्म 20 साल बाद वहीं हुआ था।
- **स्वास्थ्य सुविधाओं तक खराब पहुंच:** दूरदराज, पहाड़ी इलाकों में बस्तियों में सड़कों और एम्बुलेंस की सुविधा का अभाव है।
    - घर पर जन्म (गैर-संस्थागत प्रसव) का उच्च प्रचलन।
    - चिकित्सा सहायता के अभाव के कारण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को खतरा।
- **रोजगार की कमी:** भौगोलिक अलगाव और आधार या जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की कमी से रोजगार के अवसरों और मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुंच में बाधा आती है।

क्या किया जा सकता है?

- **मोबाइल दस्तावेजीकरण अभियान:** एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां (आईटीडीए) विस्थापित जनजातीय परिवारों के लिए लंबी यात्रा के बोझ को कम करने के लिए मोबाइल आधार केंद्र स्थापित कर रही हैं।
    - महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा आशा कार्यकर्ता परिवारों को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्रिय रूप से शामिल होंगे।
- **कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम:** डीडीयू-जीकेवाई (दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना) जैसी योजनाओं के तहत जनजातीय-केंद्रित आजीविका और कौशल विकास पहल शुरू करना।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच:** प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर और बाल देखभाल सेवाओं के साथ मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां (एमएचयू) स्थापित करें।
    - मातृत्व लाभ और एम्बुलेंस कनेक्टिविटी के साथ संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करें।

  - सांस्कृतिक अंतर को पाटने और विश्वास को बढ़ाने के लिए स्थानीय जनजातीय महिलाओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित करें।
- **सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकीकरण:** स्थानीय शासन (पेसा अधिनियम) और वन संरक्षण (एफआरए अधिनियम) में जनजातियों को शामिल करना।
  - जागरूकता और संवेदनशीलता अभियान के माध्यम से भेदभाव और बहिष्कार को संबोधित करना।

स्रोत: **The Hindu: Call for permanent settlement for tribals**

भारत: एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र

संदर्भ

2040 तक उच्च आय वाले देशों में 160 मिलियन कर्मचारियों की कमी हो सकती है। भारत अपने युवा कार्यबल के साथ वैश्विक प्रतिभा केंद्र बन सकता है, जिससे नौकरियां पैदा होंगी और वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा।

वैश्विक श्रम की कमी और भारत के लिए अवसर -

- **उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कर्मचारियों की कमी**: विकसित देशों को स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, शिक्षा और उद्योग जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- **भारत का युवा कार्यबल**: भारत में एक बड़ी, युवा आबादी है जो वैश्विक श्रम मांगों को पूरा करने में सक्षम है - लेकिन केवल 1.3% विदेश प्रवास करते हैं, जो मैक्सिको (8.6%) या फिलीपींस (5.1%) जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है।
- **धन प्रेषण के माध्यम से आर्थिक लाभ**: भारतीय प्रवासी प्रतिवर्ष 125 बिलियन डॉलर घर भेजते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद में 3% का योगदान देता है - जो किसी भी एकल निर्यात क्षेत्र से अधिक है।
- **प्रवास के माध्यम से गरीबी में कमी**: एक वैश्विक अध्ययन से पता चलता है कि धन प्रेषण में 10% की वृद्धि से निम्न आय वाले देशों में गरीबी में 3.5% की कमी आ सकती है।

भारत की वैश्विक कार्यबल उपस्थिति बनाने के लिए सात कदम -

- **प्रवासन शासन को मजबूत करना**: लक्षित बाजारों की पहचान करने, प्रवास समझौतों पर हस्ताक्षर करने और वैश्विक मांग के साथ कौशल का मिलान करने के लिए विदेश मंत्रालय की प्रवास शाखा को मजबूत करें। राज्यों को नैतिक भर्ती और श्रमिक सुरक्षा में सहायता करनी चाहिए। विदेशों में भारतीय दूतावासों को समर्पित प्रवासन सहायता डेस्क स्थापित करने चाहिए। भारत फिलीपींस की बहु-स्तरीय प्रवासन सहायता प्रणाली से प्रेरणा ले सकता है।
- **शिक्षा को वैश्विक रोजगार बाज़ारों के साथ जोड़ना**: भारतीय शिक्षा प्रणाली में विदेशी भाषाओं और अंतर्राष्ट्रीय कौशल को शामिल करना। प्रमुख गंतव्य देशों के साथ संयुक्त प्रमाणन और योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता को सुगम बनाना।
- **प्रवासन लागत में कमी लाना**: वर्तमान लागत ₹1-2 लाख (जीसीसी) से लेकर ₹5-10 लाख (यूरोप) तक है, इसलिए भारत को फिलीपींस शैली का ईएसए-वेतन मॉडल लागू करना चाहिए, जहां लाइसेंस प्राप्त भर्तीकर्ता या नियोक्ता प्रस्थान-पूर्व के प्रमुख व्ययों का वहन करते हैं।
- **द्विपक्षीय समझौतों का विस्तार**: वीज़ा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए जी2जी प्रवासन समझौतों को सक्रिय रूप से सुरक्षित करना, भारतीय योग्यताओं को मान्यता प्रदान करना सुनिश्चित करना तथा विदेशों में भारतीय कर्मचारियों के सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण को आसान बनाना।
- **राष्ट्रीय गतिशीलता निकाय की स्थापना**: विदेशी भर्ती को मानकीकृत करने, नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने, प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने तथा सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एक उद्योग-व्यापी संस्था का निर्माण करना।
- **विदेशों में प्रवासी कल्याण सुनिश्चित करना**: आईएलओ मानकों के अनुरूप उचित मजदूरी, समय पर भुगतान, पर्याप्त आवास, स्वास्थ्य पहुंच, कानूनी सहायता और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **वापस लौटे प्रवासियों के एकीकरण को सुगम बनाना**: पुनः एकीकरण सहायता और घरेलू विकास में योगदान करने के अवसर प्रदान करके वापस लौटे प्रवासियों के कौशल और वैश्विक अनुभव का लाभ उठाना।

स्रोत: **Indian Express: India can use the legal migration route to leverage its demographic dividend**

केस स्टडी

करा‍ड, महाराष्ट्र स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ

भारत में सैनिटरी कचरे का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एक उपेक्षित पहलू बना हुआ है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय गिरावट, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और सामाजिक कलंक पैदा होते हैं। **महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक छोटा शहर कराड सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे का 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण करके एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है।**

कराड मॉडल की मुख्य विशेषताएं -

- **दैनिक अपशिष्ट संग्रहण:** घरों, क्लीनिकों और अस्पतालों से प्रतिदिन 300-350 किलोग्राम स्वच्छता अपशिष्ट एकत्र किया जाता है।
    - स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट के लिए अलग डिब्बों से सुसज्जित कचरा संग्रहण वाहन।
- **सामुदायिक सहभागिता एवं जागरूकता:** सैनिटरी अपशिष्ट को कलंकमुक्त करने के लिए लक्षित आईईसी अभियान, कार्यशालाएं और सार्वजनिक पहुंच।
    - सुरक्षित निपटान प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला समूहों का गठन।
    - महिलाओं द्वारा उचित तरीके से मल-त्याग सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक शौचालयों में लाल कूड़ेदान रखे गए।
- **स्कूल पहल:** सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों और इन्सिनरेशन(Incineration) मशीनों को बढ़ावा देना।
    - किशोरियों में स्वच्छतापूर्ण निपटान की आदतों को प्रोत्साहित करना।
- **अवसंरचना एवं निपटान तंत्र:** अपशिष्ट को कराड अस्पताल एसोसिएशन के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से स्थापित एक सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) में भेजा जाता है।
    - 1200°C पर **इन्सिनरेशन** से पूर्ण कीटाणुशोधन सुनिश्चित होता है तथा संदूषण न्यूनतम होता है।
    - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) प्रणालियों से जुड़ी वास्तविक समय उत्सर्जन निगरानी।

नवीन दृष्टिकोण -

- **पीपीपी मॉडल:** नगर परिषद के लिए परिचालन लागत में कमी; उपचार का काम निजी भागीदार संभालेंगे।
- **महिला-केन्द्रित दृष्टिकोण:** अपशिष्ट जागरूकता और प्रबंधन में परिवर्तन एजेंट के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाया गया।
- **उच्च तकनीक निगरानी:** निरंतर उत्सर्जन निगरानी से पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित हुआ।

प्रभाव

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ:** रोग संचरण का कम जोखिम तथा सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य स्थितियां।
- **पर्यावरणीय लाभ:** खुले में कूड़ा फेंकने और भूजल प्रदूषण की रोकथाम।
- **सामाजिक उत्थान:** वर्जनाओं को तोड़ना, मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विशेष रूप से महिलाओं और किशोरों के बीच।
- **स्केलेबल एवं प्रतिकृति योग्य:** अन्य छोटे एवं मध्यम आकार के शहरी क्षेत्रों के लिए एक व्यवहार्य टेम्पलेट प्रदान करता है।

शासन और नीति के लिए महत्वपूर्ण बातें -

- जागरूकता, बुनियादी ढांचे और संस्थागत सहयोग को मिलाकर एकीकृत दृष्टिकोण से संवेदनशील अपशिष्ट मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।

- विशिष्ट अपशिष्ट उपचार सेवाओं के लिए पीपीपी मॉडल व्यवहार्य हैं।
- सामुदायिक भागीदारी और लिंग-संवेदनशील रणनीतियाँ शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों की सफलता और स्थिरता को बढ़ाती हैं।

स्रोत: PIB: Karad, Maharashtra has set a benchmark in sanitary waste management by ensuring the safe disposal of sanitary waste